# शासन ने मांगी है शिक्षकों, प्राचार्यों की सैलरी स्लिप आधार कार्ड की कॉपी, बैंक का स्टेटमेंट <br> शिक्षकों का ब्यौरा नहीं दे पा रहे कॉलेज संचालक 

अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर।
सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए शासन ने शिक्षकों की सैलरी स्लिप, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट समेत कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। शासन का यह आदेश कॉलेज संचालकों के लिए फांस बन गया है। वजह यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं, जहां केवल कागजों पर शिक्षक काम कर रहे हैं। लिहाजा, उनके दस्तावेज उपलब्ध कराना कॉलेज संचालकों के लिए बहुत मुश्किल है। नतीजा यह है कि सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से संबद्ध लगभग एक हजार कॉलेजों में से सिर्फ 40 ने ही दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से एक हजार से अधिक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज संबद्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में ऐसे कॉलेज हैं, जहां न तो शिक्षक हैं और न ही प्राचार्य। कई कॉलेजों की शिकायत होने के बाद शासन ने सखती दिखाई है। पंद्रह दिन पहले क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने सभी कॉलेजों से कॉलेज में कार्यरत् शिक्षकों की विषयवार संख्या, सैलरी का विवरण, बैंक का स्टेटमेंट, आधार कार्ड नंबर समेत कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। यह भी कहा गया था कि तीन दिन के भीतर विवरण उपलब्ध कराएं, लेकिन पंद्रह बीत जाने के बाद महज 40 कॉलेजों ने विवरण उपलब्ध कराया है।

## फर्जी लिस्ट से नहीं चलेगा काम

शिक्षकों के नाम की फर्जी लिस्ट तो सभी के पास है, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट मुसीबत बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कॉलेजों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के नेट क्वालीफाइड शिक्षकों का नाम कागजों पर चल रहा है। इनके नाम का इस्तेमाल करने के लिए कुछ धनराशि इनको एक बार में दी जाती है। बकाया बिना शिक्षकों के ही काम चलाया जाता है।

शासन के आदेश पर सभी कॉलेजों में
शिक्षकों का संपूर्ण विवरण गांगा गया है, लेकिन अभी तक महज 40 कॉलेजों ने ही विवरण दिया है। बकाया कॉलेजों को अब

> नोटिस दिया जाएगा।

डॉ. अनिल कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
नेट की अनिवार्यता होने से सेल्फ फाइनेस कॉलेज और एडेड दोनों ही कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। सरकार को शिक्षक भर्ती में कोई दूसरा विकल्प निकालना चाहिए।
विनय त्रिवेदी, अध्यक्ष, उप्र. सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन

